



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 198-2024/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024 (AGRAHAYANA 20, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 11 दिसंबर, 2024

**संख्या 40/जीएसटी-2.—** चूंकि, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 174 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8) के उपबन्धों को धारा 174 की उप-धारा (2) के अधीन यथा व्यावृत्त कार्यवाहियों के अध्वधीन निरसित किया गया था;

और चूंकि, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 174 की उप-धारा (2) के तृतीय परन्तुक के अधीन उपबन्ध किया गया है कि सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो इसे किसी कठिनाई, जो इस उप-धारा द्वारा यथा व्यावृत्त उक्त निरसित या संशोधित अधिनियम की कार्यवाहियों को प्रभावी रूप देने में उत्पन्न हो सकती हैं, को दूर करने के लिए आवश्यक समझे;

और चूंकि, निम्नलिखित पैरों में वर्णित कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रक्रियाएं और उपाय प्रदान करना है। प्रारंभ में, हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) को उपयोग या बिक्री के लिए मोटर वाहन और अन्य वस्तुओं के उपयोग या उपभोग तथा उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए हरियाणा राज्य के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के लिए अधिनियमित किया था। उक्त अधिनियम दिनांक 19 सितंबर, 2000 को अधिसूचित किया गया था और इसके अधीन हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर नियम, 2001 बनाए गए थे और दिनांक 14 जून, 2001 को अधिसूचित किए गए थे। तथापि, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) की संवैधानिक वैधता को सिविल रिट याचिका संख्या 6630 ऑफ 2000 मैसर्ज जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड के माध्यम से माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) के उपबन्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 और 304 (क) का उल्लंघन है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.12.2001 को उक्त याचिका खारिज कर दी और हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) की वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित मापदंडों के अनुसार यह अधिनियम प्रतिपूरक प्रकृति का था;

और चूंकि, उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21 दिसंबर, 2001 को सिविल अपील संख्या 3453 ऑफ 2002—मैसर्ज जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों की पीठ के समक्ष भेजा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अतियाबारी टी कंपनी लिमिटेड बनाम असम राज्य और अन्य [(1961)1 एससीआर 809] और ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य [(1963)1 एससीआर 491] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित व्याख्या को बरकरार रखा और तदनुसार इस निर्णय के मद्देनजर मामलों को निर्णित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नियमित पीठ ने मामले को वापस माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय को भेजा, जिसमें कहा गया कि संवैधानिक पीठ द्वारा स्थापित सिद्धांतों के मद्देनजर हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास

कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) के प्रतिपूरक प्रकृति स्वरूप का पुनः परीक्षण किया जाए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को बरकरार रखा है और उच्च न्यायालय को सलाह दी है कि वह संबंधित याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में अभिलेख पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के बाद मामले का निपटारा करे;

और चूंकि, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 14 मार्च, 2007 के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) के अधीन लागू कर प्रणाली, जिंदल स्टेनलेस (2) और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2006) 7 एससीसी 241 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा अधिकथित मापदण्डों के अनुसार प्रतिपूरक स्वरूप की नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) को अधिकारातीत घोषित कर दिया तथा यह निर्णय दिया गया कि राज्य सरकार, हरियाणा राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले माल पर कर नहीं लगा सकती है;

और चूंकि, हरियाणा सरकार ने दिनांक 16 अप्रैल, 2008 को हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8) अधिनियमित किया। जिसके द्वारा हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) द्वारा कर संग्रहण को वैधता दी गई। विभाग द्वारा हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8) के अधीन नियमों को अधिसूचित करने की कार्यवाही की जा रही थी, परन्तु इण्डियन ऑयल निगम लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक प्रथम दिसम्बर, 2008 द्वारा हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था;

और चूंकि, विभाग ने माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक प्रथम अक्टूबर, 2008 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में इसे संवैधानिक पीठ को संदर्भित किया और अंततः दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के निर्णय द्वारा 7:2 के बहुमत से यह माना गया कि राज्यों को प्रवेश कर लगाने का कानूनी अधिकार है और प्रवेश कर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के अधीन व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं है और ऐसे उपाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 304(क) का भी उल्लंघन भी नहीं करते हैं। उक्त वाद के दौरान, आदेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं से कोई वसूली नहीं की जाएगी और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे एक वचनबद्धता दायर करें कि वाद हारने की स्थिति में वे सम्बन्धित राज्यों को ब्याज सहित लागू कर की राशि का भुगतान करेंगे। उक्त निर्णय जय प्रकाश (पूर्व) के महेनजर, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर नियम, 2001 का उपयोग हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008 (2008 का 8) के अधीन भी किया जा सकता था। यदि ये नियम (हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास नियम, 2001) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008 (2008 का 8) के उपबन्धों के साथ असंगत नहीं हैं, परन्तु प्रथम जुलाई, 2017 से हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के लागू होने के बाद दिनांक 30 जून, 2017 से हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8) निरसित कर दिया गया;

और चूंकि, उपरोक्त वर्णित तथ्यों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णयों और विधिक उपबन्धों के दृष्टिगत, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8) के उद्देश्यों/प्रयोजनों को पूरा करने और उक्त अधिनियम के अधीन लम्बित कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 174 हरियाणा माल और सेवा कर (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2024 जारी करने का निर्णय लिया गया है;

इसलिए, अब, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 174 की उप-धारा (2) के तृतीय परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:-

1. (1) यह आदेश हरियाणा माल और सेवा कर (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2024 कहा जा सकता है।
- (2) यह आदेश 16 अप्रैल, 2008 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. (1) इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8);
  - (ख) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय है, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के अधीन यथा परिभाषित प्राधिकारी;
  - (ग) "प्राधिकृत बैंक" से अभिप्राय है, अधिनियम या इस आदेश के अधीन भुगतानयोग्य किसी भी देय, फीस या राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अनुसूचित बैंक या इसकी सहायिकी;
  - (घ) "परिमण्डल" से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, जिले के प्रभारी उप-आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा सम्बन्धित जिले में सीमांकित कोई परिमण्डल;
  - (ङ) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इस आदेश से संलग्न प्ररूप;

- (च) "सरकारी खजाना" से अभिप्राय है, स्थानीय क्षेत्र, जिसमें सम्बद्ध आयातकर्ता का राज्य में कारबार का अपना स्थान अथवा मुख्यालय है, में स्थित सरकारी खजाना अथवा उप-खजाना अथवा भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा अथवा सहायिकी, यदि वह शाखाएं हैं तथा वहां कोई राशि वसूल की जाती है या संगृहीत की जाती है, राज्य में स्थानीय क्षेत्र, जिसमें राशि वसूल की जाती है, अथवा संगृहीत की जाती है;
- (छ) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से अभिप्राय है, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के अधीन यथा परिभाषित प्राधिकारी;
- (ज) धारा से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा;
- (झ) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के अधीन यथा परिभाषित प्राधिकरण;

(2) इस आदेश में प्रयुक्त किन्तु इसमें अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में या हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) और इसके अधीन बनाए गए नियमों में दिए गए हैं।

3. (1) धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 4 के अधीन स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए दायी प्रत्येक आयातकर्ता पंजीकरण के लिए दायी होने के तीस दिन के भीतर अथवा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, जो भी बाद में हो, प्ररूप ई0टी0-1 में परिमण्डल के निर्धारण प्राधिकारी को पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(2) पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, एक सौ रूपए तथा ऐसी अतिरिक्त राशि, जो प्रत्येक प्रति के लिए पचास रूपए की दर से कारबार के अतिरिक्त स्थान को कवर करने के लिए अपेक्षित है, के लिए निर्धारण प्राधिकारी के पक्ष में सरकारी खजाना से एक रसीद अथवा क्रास डिमांड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश के साथ होगा।

(3) आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारण प्राधिकारी, यदि आयातकर्ता पहले ही हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 (1973 का 20) के अधीन पंजीकृत है, तो उसका तुरन्त पंजीकरण करेगा तथा किसी अन्य आयातकर्ता की दशा में, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के बाद, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि आवेदन में दिए गए ब्यौरे सही तथा पूर्ण हैं, आयातकर्ता का पंजीकरण करेगा तथा प्ररूप ई0टी0-2 में एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र देगा तथा उसमें वर्णित राज्य के भीतर मुख्यालय से भिन्न राज्य के भीतर कारबार के प्रत्येक स्थान के लिये ऐसे पंजीकरण की एक प्रति भी देगा। ऐसा पंजीकरण आयातकर्ता द्वारा, इस अधिनियम तथा इस आदेश के उपबन्धों तथा प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए रखा जाएगा।

(4) जब निर्धारण प्राधिकारी की संतुष्टि नहीं होती है कि आवेदन में दिए गए ब्यौरे सही तथा पूर्ण नहीं हैं, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदन को अस्वीकृत करेगा:

परन्तु ऐसी अस्वीकृति, आवेदक को मामले में सुनवाई का अवसर देने से पूर्व नहीं की जाएगी।

(5) इस आदेश के खंड (3) के उप-खंड (3) के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र, प्रमाण-पत्र में वर्णित मुख्यालय, यदि कोई हो, (जो आयातकर्ता द्वारा घोषित किया जाना है) सहित प्रत्येक कारबार के परिसरों के भीतर, सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(6) प्रत्येक पंजीकृत आयातकर्ता, जो अपने कारबार को बन्द कर देता है या का अन्तरण कर देता है या अन्यथा अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करवा लेता है, पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा उसको दी गई उसकी प्रतियां, यदि कोई हों, तुरन्त निर्धारण प्राधिकारी को सौंप देगा।

(7) जहां इस आदेश के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र गुम, नष्ट, विरूपित या विकृत हो जाता है, तो निर्धारण प्राधिकारी, यदि वह ऐसी हानि, नष्ट, विरूपण या विकृति आदि से संतुष्ट हो जाता है, पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि प्रदान करेगा।

(8) पंजीकृत व्यवहारी, जो हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 (1973 का 20) से हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में स्थानांतरित हो गए हैं या हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के साथ-साथ हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) के अधीन पंजीकृत हो गए थे, उन्हें अधिनियम के अधीन डीमड पंजीकृत आयातकर्ता माना जाएगा, यदि वे अधिनियम या इस आदेश के उपबन्धों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मामलों में, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन जारी किए गए व्यवहारी की कर पहचान संख्या को अधिनियम के अधीन उक्त आयातकर्ता की पंजीकरण संख्या के रूप में माना जाएगा।

4. (1) जहां आयातकर्ता, अधिनियम के अधीन उसे दिये गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन करवाना चाहता है, वहां वह ऐसे विशिष्ट मामलों जिनके संबंध में वह ऐसा संशोधन चाहता है तथा उसको दिए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित कारणों को बताते हुए इस प्रयोजन के लिए ऐसा होने के तीस दिन के भीतर निर्धारण प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा ऐसा प्राधिकारी, यदि दिए गए कारणों से संतुष्ट हो जाता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र में तथा उसको दी गई उसकी प्रतियों, यदि कोई हों, में ऐसे संशोधन कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे:

परन्तु इस प्रकार किया गया संशोधन, अधिनियम या इस आदेश के उपबन्धों से असंगत नहीं होगा।

(2) अधिनियम या इस आदेश के उपबन्ध ऐसे संशोधित प्रमाण-पत्र और उसकी प्रतियों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मूल प्रमाण-पत्र और उसकी प्रतियों के संबंध में लागू होते।

5. (1) अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति, आयातकर्ता द्वारा निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्:-

- (क) उक्त प्राधिकारी द्वारा नियत राशि, सरकारी खजाने में प्रतिभूति के रूप में जमा कराते हुए; या
- (ख) डाकघर बचत बैंक में प्रतिभूति की राशि जमा कराते हुए तथा उक्त प्राधिकारी के पास, पास बुक गिरवी रखते हुए तथा उसे जमा कराते हुए; या
- (ग) उक्त प्राधिकारी द्वारा नियत प्रतिभूति की राशि मांगने पर राज्य सरकार को भुगतान करने के लिए सहमत होते हुए, उक्त प्राधिकारी को, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक से गारन्टी देकर; या
- (घ) समुचित मूल्य के किसी न्यायिकेतर पेपर पर प्ररूप ई0 टी0 7 में उक्त प्राधिकारी की सतुष्टि के लिए प्रतिभूति की राशि के लिए ऋणशोधकम प्रतिभूति सहित स्वीय बंधपत्र देते हुए; या
- (ङ) भारत सरकार, राज्य सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए ऐसे बचत प्रमाणपत्र या बांड या सावधि जमा रसीदें प्रस्तुत करके और उन्हें उक्त प्राधिकारी के पास गिरवी रखकर जमा कर सकते हैं; या आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास गिरवी रखते हुए।

(2) अधिनियम के अधीन प्रस्तुत की गई प्रतिभूति को तब तक पूर्ण रूप में बनाए रखा जाएगा जब तक पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रभावी रहे।

(3) प्रस्तुत की गई प्रतिभूति, किसी कर, ब्याज अथवा शास्ति या किसी अन्य देय राशि के भुगतान की चूक की दशा में ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति आदि के लिए समायोजित की जा सकती है। निर्धारण प्राधिकारी किसी ऐसी दशा में, जहां ऐसा समायोजन किया गया है बकाया देयों हेतु राशि समायोजित राशि करने के लिए नई प्रतिभूति अथवा अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग कर सकता है:

परन्तु इस उप-खण्ड के अधीन तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रभावित आयातकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

6. (1) यदि कोई आयातकर्ता, राज्य में कारबार के एक से अधिक स्थान रखता है, तो कारबार के ऐसे सभी स्थानों के संकलित सकल आवर्त, कारबार के सकल आवर्त के रूप में लिए जाएंगे।

(2) अधिनियम या इस आदेश में विनिर्दिष्ट सभी विवरण तथा विवरणियां, उप-खण्ड (1) में निर्दिष्ट आयातकर्ताओं की दशा में, राज्य में मुख्यालय द्वारा परिमण्डल, जिसमें ऐसा मुख्यालय स्थित है, के निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी तथा जिसमें उसके कारबार की सभी शाखाओं के आवर्त का योग शामिल होगा।

7. (1) प्रत्येक पंजीकृत आयातकर्ता तथा प्रत्येक आयातकर्ता जिसका पंजीकरण के लिए आवेदन निर्धारण प्राधिकारी के पास लंबित है, परिमण्डल के निर्धारण प्राधिकारी को दोहरी प्रति में प्ररूप ई0 टी0 3 में प्रत्येक तिमाही के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा ताकि अवधि, जिससे विवरणी सम्बन्धित है, की समाप्ति के बाद एक मास के भीतर यह इसके पास पहुंच जाए:

परन्तु परिमण्डल निर्धारण प्राधिकारी कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी पंजीकृत आयातकर्ता को मासिक विवरणियां दायर करने के लिए निदेश दे सकता है:

परन्तु यह और कि ऐसे कोई भी निदेश आयातकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना जारी नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि प्रत्येक आयातकर्ता, जो किसी भी समय, अपना कारबार बन्द या समाप्त कर देता है, निर्धारण प्राधिकारी को, ऐसे बन्द या समापन की तिथि से तीस दिन के भीतर उस अवधि तक के लिए तथा बन्द या समापन की तिथि को सम्मिलित करते हुए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक आयातकर्ता, जो उप-खण्ड (1) के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत करता है, तो यह विवरणी के साथ, अधिनियम या इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार देय कर की पूर्ण राशि के लिए निर्धारण प्राधिकारी के पक्ष में सरकारी खजाने से कर भुगतान रसीद, क्रॉसड डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश प्रस्तुत करेगा।

8. (1) जहां कोई आयातकर्ता विवरणी दायर करने की नियत तिथि से नब्बे दिन के भीतर इसे दायर करने में असफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी, अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से निर्धारण करते समय, किसी प्रतिकूल साक्ष्य की अनुपस्थिति होते हुए भी मान लेगा कि निर्धारण के अधीन अवधि के लिए आयातकर्ता का आवर्त पूर्व वर्ष के अनुरूप अवधि के दौरान या हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के अधीन उससे कम नहीं हुआ है।

(2) यदि किसी मामले में, निर्धारण प्राधिकारी, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत की गई या किसी नोटिस के उत्तर में प्रस्तुत की गई या इस आदेश के अधीन अपेक्षित विवरणी में दर्शाए गए से भिन्न किसी आवर्त/आंकड़े के निर्धारण का प्रस्ताव करता है, तो वह अपने कारणों को लिखित में दर्ज करेगा और तदनुसार निर्धारिती को सूचित करेगा।

(3) निर्धारण करने के बाद, यदि निर्धारण प्राधिकारी को यह पता चलता है कि ऐसी कोई राशि अधिनियम या इस आदेश के उपबन्धों के अधीन किसी भुगतानयोग्य कर में से कटौती करने बाद आयातकर्ता की ओर देय है, तो वह आयातकर्ता

को प्ररूप ई0 टी0 4 में एक नोटिस ऐसे तामील करेगा तथा निर्धारिती नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर तथा रीति में मांगी गई राशि का भुगतान करेगा। यदि अन्तिम निर्धारण पर देय कर पहले से भुगतान किए गए कर से कम है, तो वह निर्धारिती के विकल्प पर, प्रतिदाय राशि के लिए पंजाब समनुषंगी खजाना नियम के अधीन विहित प्ररूप एस0टी0आर0 34 में वसूली भुगतान आदेश या प्ररूप ई0टी0 5 में प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी करेगा। यदि अन्तिम निर्धारण पहले से भुगतान किए गए कर के यथावत बराबर है, तो निर्धारण प्राधिकारी निर्धारिती को निर्धारण आदेश की प्रति देगा:

परन्तु निर्धारिती को प्रतिदेय आधिक्य कर/राशि को इस अधिनियम के अधीन प्रथमतया उसकी ओर देय किसी अन्य राशि के मद्दे समायोजित किया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए प्ररूप ई0टी0 5 में प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक लाख रुपए से अधिक की कोई राशि का प्रतिदाय जिले के प्रभारी उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा, जो/आगे आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि प्रतिदेय राशि तीन लाख रुपए से अधिक है।

9. (1) किसी अवधि के लिए कर के लिए दायी आवर्त की संगणना करने में कोई आयातकर्ता उस अवधि के दौरान अपनी सकल आवर्त में से निम्नलिखित कटौती कर सकता है,—

- (क) अधिनियम की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट माल का मूल्य;
- (ख) क्रय के रूप में किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र से प्राप्त की गई चीनी का मूल्य;
- (ग) माल का मूल्य, जो बिना प्रयोग, उपभोग या विक्रय के स्थानीय क्षेत्र के बाहर परिदत्त किया गया है;
- (घ) माल का मूल्य, जो या तो उसी रूप में या किसी अन्य रूप में, अधिनियम के अधीन एक बार कर के अध्वधीन हो;
- (ङ) माल का मूल्य, जिस पर मूल्य वर्धित कर (जिसमें क्रय कर सम्मिलित है) उसी रूप में या किसी अन्य रूप में, राज्य को भुगतान किया गया हो या भुगतानयोग्य हो गया हो;
- (च) विनिर्माण अथवा माल के प्रसंस्करण में प्रयोग हेतु पट्टे पर लाए गए या प्राप्त किए गए संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर तथा यंत्रों का मूल्य;
- (छ) स्थानीय क्षेत्र में पुनः विक्रय अथवा विनिर्माण अथवा माल के प्रसंस्करण में उपयोग अथवा उपभोग के लिए लिया गया माल, जो स्टॉक में उसी रूप में या भिन्न रूप में छोड़ दिए गए माल का मूल्य, सिवाय जब अधिनियम के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण—पत्र रद्द किया गया हो; तथा
- (ज) स्थानीय क्षेत्र में माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर तथा यंत्रों का मूल्य, जो जब अधिनियम के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाण—पत्र रद्द किया गया हो, के सिवाय पूंजीगत किया गया हो:

परन्तु वह उपरोक्त (क) से (ज) के दावे के सम्बन्ध में (संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर तथा यंत्र सहित जहां कहीं भी लागू है) उस अवधि के लिए अपनी विवरणी के साथ ऐसे माल की सूची, जिसमें उनका ब्यौरा, मात्रा, मूल्य, स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश अथवा बाहर भेजने की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, विक्रयाधिकार पत्र, परिदान नोट, खरीद बीजक, अन्तरण नोट और ऐसे माल का हक अथवा कब्जा दर्शाते हुए, अन्य दस्तावेज माल की रसीद, रेलवे रसीद इत्यादि, जिसके द्वारा ऐसा माल स्थानीय क्षेत्र में लाया गया था या बाहर भेजा गया था, जैसी भी स्थिति हो, या परिवहन किया गया था, मूल्य वर्धित कर के भुगतान (जिसमें क्रय कर सम्मिलित है) अथवा ऐसे माल के सम्बन्ध में हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर जहां कहीं भी इनका दावा किया गया है, संलग्न करेगा।

(2) निर्धारण प्राधिकारी, किसी आयातकर्ता से अधिनियम या इस आदेश के अधीन विनिर्दिष्ट सूचियों या इसमें की गई प्रविष्टियों की सत्यता तथा सहीपन के बारे में स्वयं की संतुष्टि के लिए इस अधिनियम तथा इस आदेश या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन कारबार के सामान्य अनुक्रम में उस द्वारा किसी भी रूप में बनाए गए या उस द्वारा बनाए जाने के लिए अपेक्षित कोई अभिलेख, लेखा पुस्तिका, विवरण, सूची, घोषणा, प्रमाण—पत्र या अन्य सुसंगत दस्तावेज इसके सम्मुख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। वह ऐसी सूचियों या उन में की गई प्रविष्टियों की सत्यता तथा सहीपन की जांच के लिए किसी अन्य व्यक्ति से किसी सुसंगत साक्ष्य की मांग भी कर सकता है।

10. (1) कोई निर्धारिती, किशतों द्वारा कर के बकायों, ब्याज अथवा शास्ति का भुगतान करने के लिए इस आदेश के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप ई0टी0 4 में मांग नोटिस की तामील की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदन कर सकता है।

(2) उप—खंड (1) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:

- (क) पांच लाख रुपये से अधिक की किशतों द्वारा बकायों का भुगतान या अवधि, जिसमें चौबीस मास से अधिक किशतों द्वारा बकायों का भुगतान किया जाता है, के मामले में आयुक्त; तथा
- (ख) सभी अन्य मामलों में, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त।

(3) इस खंड के अधीन उक्त प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उप-खंड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि में छूट दे सकता है यदि जहां यह पाया जाता है कि किशतों को देने के लिए आवेदन करने में देरी निर्धारित के नियन्त्रण से बाहर के कारणों से हुई है।

(4) उप-खंड (2) के अधीन किशतें देना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:-

- (क) कि निर्धारित बकायों का किशतों द्वारा भुगतान करने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी की संतुष्टि अनुसार पर्याप्त प्रतिभूति देता है;
- (ख) कि निर्धारित भुगतान की तिथि तक अशोधित बकायों की राशि के सम्बन्ध में धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक अनुमत किशत प्रभार्य ब्याज सहित भुगतान करता है;
- (ग) कि निर्धारित इस प्रभाव की घोषणा करता है कि किशतों द्वारा बकायों के भुगतान के लिए उप-खंड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों से भिन्न प्राधिकारियों को कोई अन्य आवेदन नहीं किया गया है।

(5) उप-खंड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसे उप-खंड (1) के अधीन आवेदन किया जाता है, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, लिखित में आदेश द्वारा, उप-खंड (4) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए निर्धारित को ऐसी किशतों में तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो इसके आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, बकायों के भुगतान के लिए अनुमत कर सकता है।

(6) यदि निर्धारित आदेश या उप-खंड (4) में विनिर्दिष्ट किन्ही शर्तों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या इस आदेश के उपबन्धों के अनुसरण में भुगतान करने में कोई चूक करता है, ऐसी चूक की तिथि पर भुगतान नहीं की गई शेष सम्पूर्ण राशि, ब्याज सहित, अधिनियम तथा इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार, एकमुश्त में तुरन्त वसूली योग्य होगी।

**11.** (1) अधिनियम अथवा इस आदेश के अधीन भुगतानयोग्य कर, ब्याज तथा शास्ति अथवा कोई अन्य राशियां आयातकर्ता द्वारा निम्नलिखित रूप में भुगतान की जाएंगी,-

- (i) सरकारी खजाने में प्रेषण द्वारा; अथवा
- (ii) निर्धारण प्राधिकारी के पक्ष में क्रास डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश द्वारा।

(2) अधिनियम के अधीन या इस आदेश के अधीन सरकारी खजाने में किए गए प्रत्येक भुगतान के साथ प्ररूप ई0टी0-6 में चालान संलग्न किया जाएगा।

**12.** जहां निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को प्रतिदाय अनुमत किया जाता है, ऐसा व्यक्ति, सम्बद्ध प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जो अधिनियम तथा इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के 180 दिन के भीतर प्रतिदाय जारी करेगा।

**13.** (1) अधिनियम के अधीन प्रत्येक पंजीकृत आयातकर्ता तथा स्वयं को पंजीकृत करवाने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले माल का मूल्य दर्शाते हुए अपने दैनिक संव्यवहार का वास्तविक तथा सही लेखा रखेगा और अनुरक्षित भी रखेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आयातकर्ता अथवा व्यक्ति माल के सम्बन्ध में क्रय तथा विक्रय का अलग लेखा रखेगा।

(3) प्रत्येक ऐसा आयातकर्ता अथवा व्यक्ति पंजीकरण प्रमाण-पत्र में प्रविष्ट कारबार के स्थान अथवा स्थानों पर चालू बही लेखे रखेगा।

(4) प्रत्येक ऐसे आयातकर्ता या व्यक्ति को प्रत्येक माल और प्रत्येक ऐसी किस्म के माल के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्टॉक खाता बनाए रखना होगा, जो अलग-अलग दरों पर कर योग्य है। स्टॉक खाते में माल की खरीद या प्राप्ति, उपयोग या उपभोग, बिक्री या प्रेषण और शेष स्टॉक का ब्यौरा अन्तर्विष्ट होगा।

(5) प्रत्येक आयातकर्ता प्रत्येक शाखा, डिपो अथवा गोदाम के लिए स्टॉक के सहायक लेखे रखेगा। प्रत्येक शाखा अपने निजी संव्यवहार के सम्बन्ध में अपने मुख्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए अपनाए गए ढंग में स्टॉक लेखे भी रखेगा।

(6) आयातकर्ता द्वारा रखी गई खाता बही को, जैसे ही और जब भी इस निमित्त नोटिस द्वारा अपेक्षित हो, निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

**14.** (1) अधिनियम अथवा इस आदेश के अधीन विहित सभी प्ररूपों, रजिस्ट्रों तथा अन्य दस्तावेजों में सभी प्रविष्टियां स्याही में अथवा कम्प्यूटर मुद्रित होंगी:

परन्तु जहां प्ररूप, घोषणा, विवरणी, रजिस्टर अथवा अन्य दस्तावेजों की एक ही समय में एक से अधिक प्रतियां दर्ज की जानी हैं अथवा लिखी जानी हैं, तो प्रविष्टियां किसी बाल प्वाइंट पेन अथवा टाइपराइटर अथवा कम्प्यूटर द्वारा की जा सकती हैं।

(2) ऐसे प्ररूपों, रजिस्ट्रों तथा अन्य दस्तावेजों में कोई भी प्रविष्टि मिटाई नहीं जाएगी अथवा लिप्तलेखित नहीं की जाएगी। गलत प्रविष्टियों को सत्यापनाधीन काटा जाएगा और ठीक प्रविष्टि अभिलिखित की जाएगी।

**15.** अधिनियम और इस आदेश के अन्य उपबन्धों के अधीन, अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, प्रमाणन, सन्दर्भ, सुधार या लिपिकीय तथा अकंगणित गलतियों, शपथ पर साक्ष्य लेने की शक्ति, आयातकर्ता के अवधारण की शक्ति, बैंकिंग कंपनियों इत्यादि से सूचना मांगने की शक्ति, अन्तरण कार्यवाहियों की शक्ति, प्रत्यायोजन की शक्ति, प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से हाजिरी, कारबार के परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करने, किसी आयातकर्ता या किसी निर्धारित द्वारा प्रस्तुत किए गए

दस्तावेजों को गोपनीय मानने और अन्य सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई आयातकर्ता या कोई निर्धारिती समरूप अधिकार रखेंगे और हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के अधीन आयातकर्ता के रूप में समरूप दायित्वों का निर्वहन करने हेतु बाध्य होंगे।

**16.** सरकार, धारा 25 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अधिनियम के अधीन संगृहीत कर का आबंटन/विनियोजन करते समय, अधिनियम की धारा 26 के अधीन गठित हरियाणा, व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग विकास बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करेगी।

प्ररूप ई0 टी0 1

[ देखिए खंड 3 (1) ]

हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008  
(2008 का 8) के अधीन आयातकर्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

सेवा में

निर्धारण प्राधिकारी,  
परिमण्डल \_\_\_\_\_,  
जिला \_\_\_\_\_

मैं, \_\_\_\_\_ सुपुत्र \_\_\_\_\_ कारबार में लगा हुआ हूँ जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं,

इसके द्वारा, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8) की धारा 4 के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन करता हूँ।

- 1 आवेदक का नाम तथा पूरा डाक पता (यदि उसका व्यवसाय का कोई नाम है, तो व्यवसाय नाम भी देना होगा)।
- 2 कारबार के प्रबन्धक का नाम तथा पता, यदि कोई प्रबन्धक इस प्रकार नियुक्त किया गया है।
- 3 इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता तथा प्रास्थिति (प्रास्थिति के सम्बन्ध में, बताएं क्या स्वत्वधारी, प्रबन्धक, निदेशक या भागीदार इत्यादि हैं)।
- 4 भवन का नाम तथा संख्या, वार्ड का नाम तथा संख्या, सड़क का नाम, गली का नाम इत्यादि के विवरण सहित मुख्यालय का नाम तथा पूरा डाक पता, दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, ई-मेल पता, इन्टरनेट साइट पता, यदि कोई हो, दें।
- 5 क्षेत्र में राज्य में जहां कहीं भी नगरपालिका अथवा प्रत्येक कारबार के स्थान के लिए भवन का नाम तथा संख्या, सड़क का नाम, गली संख्या, इत्यादि के ब्यौरे सहित कारबार के अन्य स्थानों का नाम तथा पूरा डाक पता, (यदि इस खाना में स्थान कम पड़ता है तो अतिरिक्त शीट प्रयोग की जा सकती है तथा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हो)।
- 6 गोदामों की पूर्ण सूची जिनमें माल भण्डारण किया गया तथा ऐसे प्रत्येक गोदाम का पता।
- 7 कारोबार के प्रारम्भ की तिथि तथा कारबार का स्वरूप।
- 8 तिथि जिसको आवेदक प्रथम बार कर भुगतान के लिए दायी हुआ।
- 9 हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र के ब्यौरे—
  - (i) कर भुगतानकर्ता की पहचान संख्या
  - (ii) वैधता की तिथि
- 10 अधिनियम के अधीन अनुमानित वार्षिक कर दायित्व।
- 11 आवेदक द्वारा अनुसरणित लेखा वर्ष।
- 12 क्या आवेदक कोई स्वत्वधारी, फर्म, कम्पनी, सोसाइटी, क्लब, व्यक्तियों का संगठन, अविभाजित हिन्दू परिवार या न्यास इत्यादि है (यहां पूरा विवरण दें)।
- 13 पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके सम्बन्ध में आवेदन किया गया है, में माल के क्रयों/स्टाक रसीदों का कुल मूल्य।

- 14 आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि तक वर्ष में माल के क्रय/स्टाक की रसीदों का वास्तविक मूल्य।
- 15 रसीद संख्या तथा तिथि के विवरण के साथ भुगतान की गई पंजीकरण फीस की राशि।
- 16 रसीद संख्या तथा तिथि, चालान संख्या तथा तिथि, चैक संख्या तथा तिथि/खजाना /बैंक इत्यादि के नाम के ब्यौरे सहित कारबार के अन्य स्थानों के लिए प्रमाण-पत्र की प्रतियों के लिए भुगतान की गई फीस की राशि/डिजिटल भुगतान।
- 17 कारबार में हित रखने वाले स्वत्वधारी/भागीदारों, सदस्यों, सभी व्यक्तियों के नाम (नामों) तथा पता (पते) (निम्नलिखित खानों के साथ अतिरिक्त शीटें प्रयोग में लाई जाएंगी, यदि आवश्यक हो)।

क्रम संख्या	प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम	पिता का नाम	आयु	प्रत्येक व्यक्ति का स्थाई पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रत्येक व्यक्ति का वर्तमान डाक पता	कारबार में प्रत्येक व्यक्ति के हित की सीमा	प्रत्येक व्यक्ति के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर सत्यापित करने वाले साक्षी का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)

**घोषणा**

मैं,-----सुपुत्र/पत्नी श्री----- इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त  
दिए गए आवेदन में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है।

स्थान:

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

तिथि:

पूरा नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

प्रास्थिति \_\_\_\_\_

(खाना संख्या 3 में दिए गए अनुसार)

(निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कार्यालय प्रयोग के लिए)

आवेदन की प्राप्ति की तिथि :

निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का स्वरूप :

आदेश की तिथि :

पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या,..... यदि जारी किया गया है :

पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि :

तिथि सहित निर्धारण प्राधिकारी  
के हस्ताक्षर

**प्ररूप ई0 टी0 2**  
**[ देखिए खंड 3 (3) ]**  
**पंजीकरण प्रमाण-पत्र**

**पंजीकरण संख्या** \_\_\_\_\_

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स \_\_\_\_\_ जिसका कारबार का स्थान/मुख्यालय \_\_\_\_\_ में स्थित है, को हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8) की धारा 4 के अधीन तथा उक्त अधिनियम तथा इस आदेश के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए पंजीकरण प्रदान किया गया है:-

1. (1) यह प्रमाण-पत्र, कारबार के परिसर के भीतर किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।  
 (2) कारबार का स्थान या अतिरिक्त कारबार के स्थानों पर दैनिक संव्यवहारों के सही लेखे रखे जाने चाहिए।  
 (3) पंजीकृत आयातकर्ता, उसके स्टॉक की जांच करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा तथा सभी युक्तियुक्त समयों पर, लेखों या अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा तथा उसके कब्जे में कोई सूचना, जो अधिनियम या नियमों के प्रयोजन के लिए इस निमित्त सशक्त अधिकारी को अपेक्षित हो, पूर्ण रूप से तथा सही रूप में प्रस्तुत करेगा।  
 (4) विहित कथन तथा विवरणियां परिमण्डल के निर्धारण प्राधिकारी को विहित समय में प्रस्तुत की जानी चाहिए।  
 (5) यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्धारण प्राधिकारी, जिसे आवेदन किया है तथा जिससे प्राप्त किया गया है, की अनुज्ञा के बिना न तो अंतरित किया जाएगा या न बेचा जाएगा या न ही इसे संशोधित किया जाएगा।  
 (6) इस प्रमाण-पत्र में सभी शुद्धियां निर्धारण प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा साक्ष्यकित की जाएंगी।  
 (7) पंजीकृत आयातकर्ता उसके प्रबन्धक, अभिकर्ता या सेवक के सभी कार्यों के लिए जिम्मेवार होगा।
2. पंजीकृत आयातकर्ता के नीचे वर्णित कारबार के अतिरिक्त स्थान हैं:-  
 (क)  
 (ख)  
 (ग)  
 (घ)
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र \_\_\_\_\_ से रद्द होने तक वैध है।
4. इस पंजीकरण प्रमाण-पत्र का धारक \_\_\_\_\_ तिथि से कर भुगतान करने का दायी होगा तथा कर विवरणी दायर करेगा तथा अधिनियम के अधीन जब तक अन्यथा निर्देशित न किया गया हो तब तक वह ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर का भुगतान त्रैमासिक आधार पर करेगा।

दिनांक

मोहर

(हस्ताक्षरित)

निर्धारण प्राधिकारी

## प्ररूप ई0 टी0 3

[ देखिए खंड 7 (1) ]

आवर्त तथा भुगतानयोग्य कर की विवरणी  
(दोहरी प्रति में प्रस्तुत की जाए)

..... से ..... तक की अवधि के लिए विवरणी

1. व्यक्तिगत ब्यौरे (स्थायी खाता संख्या, संपर्क संख्या, ईमेल आईडी आदि):
2. पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या :
3. आयातकर्ता का पूरा नाम और पता :
4. विवरणी अवधि के लिए कर के भुगतान के दायित्व की संगणना .....

माल

1. आवर्त का भाग रूप बनाने वाले माल का वर्णन (केवल मुख्य पांच बताएं)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

मद

राशि (रुपए में)

- (2) सकल आवर्त .....

(क) पूर्व अवधि से आगे लाया गया आरम्भिक स्टॉक (देखिए अधिनियम की धारा 8 के खंड (छ) का प्रथम परन्तुक):

(ख) विक्रय के लिए माल सहित किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर प्राप्त माल के मूल्य का पूर्ण योग (देखिए अधिनियम की धारा 2 के खंड (थ)

- (3) 2(क) तथा 2(ख) का जोड़

मद

राशि (रुपए में)

कटौतियां (देखिए खंड 9).....

- (4) (क) अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट माल का मूल्य:

(ख) क्रय के रूप में किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र से प्राप्त की गई चीनी का मूल्य:

(ग) माल का मूल्य जो बिना उपभोग, उपयोग या विक्रय के स्थानीय क्षेत्र से बाहर परिदत्त किया गया है:

(घ) माल का मूल्य, जो या तो उसी रूप में या किसी अन्य रूप में अधिनियम के अधीन एक बार कर के अधीन हो गया है:

(ङ) माल का मूल्य, जिस पर विक्रय कर चाहे उसी रूप में या किसी अन्य रूप में राज्य को भुगतान किया गया है या भुगतानयोग्य हो गया है:

(च) माल के विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण में प्रयोग हेतु पट्टे पर लाए गए या प्राप्त किए गए संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर तथा यंत्रों का मूल्य:

(छ) स्थानीय क्षेत्र में पुनः विक्रय के लिए या उपभोग के लिए या विनिर्माण में उपयोज्य या माल के प्रसंस्करण के लिए लाए गए या प्राप्त किए गए माल का मूल्य उसी रूप में या किसी अन्य रूप में छोड़ दिए गए

जिसमें प्रक्रिया या प्रसंस्कृत या विनिर्मित माल शामिल है का मूल्य, सिवाय जब अधिनियम के अधीन जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया गया हो:

(ज) माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में पुनः विक्रय या उपयोग या उपभोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाए गए या प्राप्त किए गए संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर तथा यंत्रों का मूल्य पंजीकृत किया गया है, के सिवाय जब अधिनियम के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया गया हो:

(झ) अधिनियम या इस आदेश के अधीन किसी अन्य कटौती का दावा (अधिनियम या आदेश के सुसंगत उपबन्ध को उद्धरित करते हुए कटौती तथा विवरणी के साथ संलग्न ब्यौरे दर्शाएँ):—

(5) 4(क) में 4 (झ) तक का जोड़ .....

करयोग्य आवर्त

(6) कर के लिए दायी माल का मूल्य (मद 3 में से मद 5 घटाएँ):.....

भुगतानयोग्य कर .....

(7) अधिनियम के अधीन लागू कर की दर से गुणा किया गया करयोग्य आवर्त कर का भुगतान:.....

(8) भुगतान करने का तरीका:

क्रम संख्या      भुगतान किया गया दिनांक  
कर/राशि (रूपए में)

खजाने का नाम तथा डिमांड ड्राफ्ट  
खजाना रसीद संख्या      संख्या

ऑनलाइन  
भुगतान      संदर्भ  
संख्या/डेबिट  
प्रविष्टि संख्या

(9) देय अतिशेष, यदि कोई हो,

(मद 6 में से मद 7 घटाएँ): \_\_\_\_\_

#### घोषणा

मैं \_\_\_\_\_सुपुत्र/पत्नी श्री\_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उक्त विवरण में प्रस्तुत की गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य तथा पूर्ण है।

स्थान :

हस्ताक्षर\_\_\_\_\_

तिथि :

पूरा पता\_\_\_\_\_

प्रास्थिति\_\_\_\_\_।

## प्ररूप ई0टी0 4

[ देखिए खंड 8 (3) तथा खंड 10 ]

हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8)  
की धारा 9 के अधीन निर्धारण तथा मांग का नोटिस

जिला

दिनांक

संख्या-----

सेवा में

-----

-----

आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष ----- के दौरान आपका मामला कर के लिए निम्न प्रकार से निर्धारित/पुनः निर्धारित किया गया है:

कर के लिए दायी के रूप में अवधारित माल का मूल्य: -----रुपए

निर्धारित कर तथा ब्याज:

(क) कर-----रुपए

(ख) ब्याज -----रुपए

(ग) अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो-----रुपए

(क, ख तथा ग) का जोड़

(घ) पहले से भुगतान की गई राशि घटाएं-----रुपए

(ङ) शुद्ध देय राशि-----रुपए

आपको इसके द्वारा, ----- रुपए (अंकों में) -----रुपए (शब्दों में) की राशि सरकारी खजाने/भारतीय स्टेट बैंक या इसकी सहायिकी या किसी अनुसूचित बैंक अथवा उसकी शाखा में ----- पर ----- (तिथि) या से पहले भुगतान करने तथा इस भुगतान के प्रमाण के रूप में ----- (तिथि) को या से पहले इसकी रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसकी चूक होने पर आप से उक्त राशि भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलीयोग्य होगी।

इस प्रयोजन के लिए प्ररूप ई0टी0-6 में चालान संलग्न है।

(हस्ताक्षर)

निर्धारण प्राधिकारी

दिनांक

निर्धारण प्राधिकारी की मोहर

जिला

**प्ररूप ई0 टी0 5**  
**[देखिए खंड 8(3)]**  
**प्रतिदाय समायोजन आदेश**

बही संख्या-----

वाऊचर संख्या----- प्रतिदाय

सेवा में

-----

----- ।

1. हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8) के अधीन ----- जिला की पंजीकरण संख्या ----- रखने वाले आयातकर्ता के (नाम) -----के-----से ----- तक की अवधि के लिए, निर्धारण अभिलेख के प्रतिनिर्देश से प्रमाणित किया जाता है कि----- रुपए (अंकों में)-----रुपए (शब्दों में) का प्रतिदाय (नाम)-----को देय है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित कर, जिसके लिए प्रतिदाय अनुज्ञात किया गया है, खजाने में जमा कर दिया गया है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत राशि के सम्बन्ध में इससे पूर्व कोई प्रतिदाय आदेश प्रदान नहीं किया गया है तथा यह प्रतिदाय आदेश मूल निर्धारण फाइल/निपटान रजिस्टर में मेरे हस्ताक्षरों के अधीन दर्ज कर दिया गया है।
4. यह प्रतिदाय-----से-----तक अथवा इसके उत्तरवर्ती किसी मास/तिमाही की अवधि के लिए उक्त आयातकर्ता से देय कर की राशि की ओर समायोजित कर दिया जाएगा।
5. आयातकर्ता उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उस मास की विवरणी के साथ इस आदेश को संलग्न करेगा जिसके विरुद्ध समायोजन वांछित है।

हस्ताक्षर

निर्धारण प्राधिकारी

जिला

तिथि

निर्धारण अधिकारी की मोहर

**प्ररूप ई0 टी0 6**  
**[ देखिए खंड 11(2) ]**  
**चालान**  
**भाग क**  
**(खजाने में रखा जाना है)**

खजाना

उप-खजाना शाखा/भारतीय स्टेट बैंक की सहायिकी/अनुसूचित बैंक या इसकी कोई शाखा

हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8) के अधीन लेखा शीर्ष "0042-माल तथा यात्रियों पर कर (1) 106-स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर: (3) - हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर" के अधीन भुगतान किए गए/जमा किए गए कर इत्यादि का बीजक

जिसके द्वारा दिया गया	पंजीकरण प्रमाण-पत्र/अनुज्ञप्ति संख्या सहित व्यक्ति का नाम, पता जिसकी ओर से राशि का भुगतान किया गया	के मद्दे भुगतान राशि (रूपए में)
--------------------------	---	---------------------------------

- |        |                             |
|--------|-----------------------------|
| (i)    | विवरणियों के अनुसार कर----- |
| (ii)   | निर्धारित कर-----           |
| (iii)  | ब्याज-----                  |
| (iv)   | शास्ति-----                 |
| (v)    | प्रशमन-----                 |
| (vi)   | पंजीकरण-----                |
| (vii)  | अनुज्ञप्ति फीस-----         |
| (viii) | प्रतिभूति-----              |
| (ix)   | अन्य फीस-----               |
| (x)    | जोड़-----                   |

तिथि-----

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी ब्यौरे सही हैं।

\* "प्रवेश कर लिपिक-----

\* "प्राप्त करना और रसीद देना

\* "निर्धारण प्राधिकारी/परिमण्डल प्रभारी-----

प्राप्त की गई राशि—	आयातकर्ता या जमाकर्ता के हस्ताक्षर
निर्धारण प्राधिकारी/परिमण्डल प्रभारी की मोहर	खजाना लेखपाल
खजांची	उप खजाना अधिकारी
खजाना/बैंक की मोहर	उप-खजाना शाखा/भारतीय स्टेट बैंक की सहायिकी/ अनुसूचित बैंक या इसकी किसी शाखा का अभिकर्ता
उप खजाना अधिकारी/खजांची,	
उप-खजाना शाखा/भारतीय स्टेट बैंक की सहायिकी/ अनुसूचित बैंक या इसकी कोई शाखा	

‘किसी आयातकर्ता या जमाकर्ता द्वारा स्वैच्छिक भुगतान की दशा में, प्रवेश कर लिपिक/निर्धारण प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

भाग ख: जिला के प्रभारी, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त को वापस किया जाए।

भाग ग: आयातकर्ता द्वारा आवेदन/विवरणी के साथ संलग्न किया जाए।

भाग घ: आयातकर्ता द्वारा रखा जाए।

टिप्पण: ई0 टी0 6 के भाग ख, ग तथा घ उसके भाग क के समरूप हैं। अतः पुनः प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

**प्ररूप ई0 टी0 7**  
**[ देखिए खंड 5(1)(घ) ]**  
**बन्धपत्र**

इस विलेख द्वारा सभी व्यक्तियों को ज्ञात हो कि मैं/हम..... (पूरा नाम तथा पता)..... पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या, यदि कोई हो..... रखता हूँ/रखते हैं तथा हरियाणा के राज्यपाल के प्रति (जिन्हें, इसमें, इसके बाद सरकार कहा गया है, जिसमें, जब तक यह संदर्भ से अपवर्जित या उसके प्रतिकूल न हों, उसके पद में उत्तरवर्ती तथा समनुदेशिती शामिल होंगे) ..... रुपए (.....रुपए) (शब्दों में) (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त राशि कहा गया है) की मांग, जिसके लिए भुगतान सरकार को किया जाएगा और वास्तव में किया जाना है, हेतु दृढ़ता से आबद्ध हूँ/हैं। मैं/हम, इन विलेखों द्वारा मुझे/हमें/मेरे/हमारे वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा विधिक प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूँ/करते हैं।

चूंकि, निर्धारण प्राधिकारी/अपील प्राधिकारी..... (स्थान का नाम) द्वारा उपयुक्त आबद्ध व्यक्तियों से, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (जिसे, इसमें, इसके बाद, "अधिनियम" कहा गया है) के अधीन उसके/उनके द्वारा भुगतानयोग्य किसी राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उक्त राशि की प्रतिभूति प्रस्तुत करने तथा सरकार को ऐसी सभी हानियों, लागतों या खर्चों की क्षतिपूर्ति करने के लिए, जो सरकार को उक्त अधिनियम के अधीन विहित रीति में, उक्त राशि का भुगतान करने के लिए, उपर्युक्त आबद्ध व्यक्तियों या उसके/उनके लिए कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की भूल, व्यक्तिगत या असफलता दिवालिएपन के कारण किसी भी प्रकार हो, उठानी पड़े या भुगतान करना पड़े, अपेक्षा की गई है:

अब उपर्युक्त लिखित बन्धपत्र की शर्त यह है कि यदि अधिनियम के अधीन विहित रीति में देय पूर्ण राशि का भुगतान उपर्युक्त आबद्ध, उसका/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा विधिक प्रतिनिधि उसकी/उनकी ओर से या उसके/उनके अधीन कार्य कर रहा कोई व्यक्ति, ऐसी मांग के लिखित रूप में होने पर तथा आबद्ध, उसके/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा विधिक प्रतिनिधि या उसकी/उनकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति पर, अधिनियम के अधीन विहित रीति में तामील किए जाने पर उक्त आबद्ध, उसका/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा विधिक प्रतिनिधि उसकी/उनकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति पर ऐसी सभी और प्रत्येक हानि, लागत या खर्चों से, जो उस अवधि के दौरान जिस में उपर्युक्त आबद्धकारी अधिनियम के अधीन भुगतान करने के लिए दायी ठहराया गया है, या उसके बाद होंगे या हों, सभी समयों पर सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा अथवा सरकार को ऐसे सभी और प्रत्येक खर्चों की लागत या नुकसान से बचाएगा, तो ऐसी स्थिति में यह बाध्यता शून्य होगी और कोई प्रभाव नहीं रखेगी, अन्यथा यह बाध्यता पूरी तरह से प्रवत और प्रभावी रहेगी और इसके द्वारा यह और करार किया जाता है कि उपर्युक्त बन्धकारी की मृत्यु/विभाजन/विनष्टिकरण/विघटन/समापन हो जाने या अधिनियम या कठिनाईयों का निवारण आदेश के अधीन दायित्व के अन्तिम रूप से समाप्त होने की दशा में, यह बन्ध-पत्र, ऐसी कोई राशि जो उपर्युक्त आबद्धकारी द्वारा भुगतान योग्य हो, या हानि, लागत या खर्चों, जो उक्त आबद्धकारी, उसके, उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा विधिक प्रतिनिधियों के दिवालिएपन के कारण हुई हो/की गई हो को वसूल करने के लिए उक्त प्राधिकारी के पास रहेगा तथा जिनका उपर्युक्त आबद्धकारी की मृत्यु/विभाजन/विनष्टिकरण/विघटन/समापन या अधिनियम या कठिनाईयों का निवारण आदेश के अधीन और उसके/उनके दायित्व के अन्तिम रूप से समाप्त होने पर पता नहीं चला है:

परन्तु सदैव यह कि इस अधिनियम के अधीन देय किसी राशि या यथापूर्वोक्त किसी हानि या नुकसान को वसूल करने के लिए किसी अन्य अधिकारी या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार इस बात के लिए स्वतंत्र होगी कि यह इस बन्धपत्र के अधीन भुगतान योग्य राशि को भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल कर लें।

जिसके साक्ष्य के प्रमाणस्वरूप उक्त.....(पूरा नाम).....ने ..... की उपस्थिति में आज..... के दिन को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और बन्धपत्र परिदत्त कर दिया है।

साक्षी:

1. .... हस्ताक्षर

2. .... प्रास्थिति

3. हम (1) .....

(2) .....

(प्रतिभूओं के नाम और पूरे पते) स्वयं को उक्त आबद्धकारी के लिए प्रतिभूतियों के रूप में, घोषित करते हैं और गारन्टी देते हैं कि उसने/उन्होंने जो पूर्वोक्त दायित्व लिया है, उसे पूरा करेगा/करेंगे तथा उसका पालन करेगा/करेंगे, हम इसके द्वारा संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक सरकार को .....रुपये) (.....रुपये) की राशि जिसके लिए पूर्वोक्त आबद्धकारी ने स्वयं को पूर्वोक्त के लिए आबद्ध किया है या ऐसी अन्य कम राशि, जो निर्धारण प्राधिकारी बन्धकारी से

पूर्वोक्त बन्धक द्वारा किसी राशि को वसूल किए जाने के लिए पर्याप्त समझें तथा जिसका भुगतान न किया गया हो तथा ऐसी हानि या नुकसान की लागत या खर्च, जो सरकार को ऐसी भूल, व्यक्तिक्रम या असफलताओं के कारण हुआ हो, किया हो या भुगतान किया हो, भुगतान करने के लिए आबद्ध करते हैं।

और हम सहमत हैं कि सरकार उक्त राशि, अपने किन्हीं अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हमसे संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक भू-राजस्वों के बकायों के रूप में वसूल कर सकती है।

और हम इसके लिए सहमत हैं कि हम में से कोई भी इस प्रतिभू-बंधपत्र को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा, सिवाय अपने ऐसा करने के आशय का निर्धारण प्राधिकारी को छह मास का एक लिखित रूप में नोटिस देकर और इस बन्धपत्र के अधीन बन्धकदार की ओर से सभी कार्यों, भूलों, व्यक्तिक्रमों असफलता तथा दिवालियापन की बाबत हमारा संयुक्त तथा पृथक दायित्व उक्त छह मास की अवधि की समाप्ति तक जारी रहेगा।

साक्षियों का नाम, पूरा पता तथा हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में प्रतिभूओं के हस्ताक्षर।

(1) हस्ताक्षर

स्थायी पता .....

(2) हस्ताक्षर

स्थायी पता.....

देविंदर सिंह कल्याण,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**  
**ORDER**

The 11th December, 2024

**No. 40/GST-2.**— Whereas under clause (ii) of sub-section (1) of section 174 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the provisions of the Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 (8 of 2008) stands repealed subject to the actions saved under sub-section (2) of section 174;

And whereas it has been provided under third proviso to sub-section (2) of section 174 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) that the Government may, by order, publish in the official Gazette make such provisions to remove any difficulty, which may arise in giving effect to the actions of the said repealed or amended Acts;

Whereas to remove the difficulties described in the succeeding paras by providing procedures and measures for resolving the same, initially, the Government of Haryana had enacted the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000) to provide for levy and collection of tax on the entry into a local area of the State of Haryana, of a motor vehicle for use or sale, and of other goods for use or consumption, therein and matters incidental thereto and connected therewith. The said Act was notified on 19th September 2000 and the Haryana Local Area Development Tax Rules, 2001 were framed thereunder and notified on the 14th June, 2001. However, the constitutional validity of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000) was challenged by M/s Jindal Strips Limited before the Punjab and Haryana High Court through CWP No. 6630 of 2000 on the ground that the provisions of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000) is violative of article 301 and article 304 (a) of the Constitution of India. The High Court dismissed the petition on 21.12.2001 and upheld the validity of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000). It was held by the Court that the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000) was compensatory in nature as per the parameters laid down by the Supreme Court;

And whereas this judgment of the High Court dated the 21st December, 2001 was challenged vide Civil Appeal No.3453 of 2002 by M/s.Jindal Stainless Ltd. before the Supreme Court of India. This case was referred to the Five Judges' Bench in the Supreme Court. The five Judges' Constitutional Bench upheld the interpretation laid down by the Apex Court in *Atiabari Tea Company Ltd. Vs. The State of Assam and Ors.*, [(1961) 1 SCR 809] and *The Automobile Transport (Rajasthan) Ltd. Vs. The State of Rajasthan and Ors.*, [(1963) 1 SCR 491] and pronounced that so long as a tax is regulatory and compensatory, it is not within the mischief of article 301 of the Constitution of India. The said judgment is reported as *Jindal Stainless Ltd. (2) Vs. State of Haryana* (2006) 7 SCC 241. And accordingly, listed the cases before the Regular Bench of Supreme Court to decide the cases in view of this judgment. The Regular Bench of the Supreme Court referred the matter back to the Punjab and Haryana High Court with the directions to re-examine the issue of compensatory nature of the said Act i.e. the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000) in the light of the principles laid down by the Constitutional Bench of the Supreme Court. Simultaneously, the Apex Court has retained the appeals and advised the Punjab and Haryana High Court to dispose of the case after granting opportunities to the respective petitioners to place material on record in the High Court;

And whereas Punjab and Haryana High Court vide judgment dated the 14th March, 2007 had come to the conclusion that the levy under the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000) was not compensatory in view of the parameters laid down by the Supreme Court Constitutional Bench in *Jindal Stainless Ltd. (2) Vs. State of Haryana*, (2006)7 SCC 241. The Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000) was declared ultra-vires and held that the State cannot levy tax on the goods entering into the State of Haryana;

And whereas the State of Haryana has enacted the Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 (8 of 2008) with effect from the 16th April, 2008 which inter alia is a validating Statute with respect to the collections that were already made under the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000). Before any rules could be notified under the Haryana Tax on Entry of Goods into the Local Area Act, 2008 (8 of 2008) which were under process, the said Act i.e. the Haryana Tax on Entry of Goods into the Local Area Act, 2008 (8 of 2008) was declared unconstitutional vide judgment dated 1st October, 2008 passed by the Punjab and Haryana High Court in the case of *Indian Oil Corporation Ltd. Vs. State of Haryana & Ors.* (2009) which has been reported as 21 VST 10 (P&H);

And whereas the department filed a SLP against this judgment dated 1st October, 2008 of the Punjab and Haryana High Court before the Apex Court. Ultimately the Hon'ble Supreme Court in case of *M/s Jai Parkash Associates Ltd VS. State of M.P. & Ors.* referred the same to the larger bench and finally vide judgment dated the 11th November, 2016, by a majority view of 7:2 has held that the States are within their legal rights to levy entry tax and that the entry tax is not a restriction on the freedom of trade and commerce of any person as envisaged under article 301 of the Constitution of India and such measures (levy of Entry Tax by the States) would not contravene article 304(a) of the Constitution of India as well. During the said litigation, vide order dated the 31st October, 2009, the Supreme Court has also directed that no recovery shall be made from the petitioners and directed the petitioners to file an

undertaking stating that in the event of losing the case they shall pay the amount of tax as applicable with interest to the respective States. In view of the said judgment [Jai Prakash (supra)], the Haryana Local Area Development Rules, 2001 could also be used under the Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 (8 of 2008) if these rules (Rules 2001) are not inconsistent with the provisions of the Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 (8 of 2008). The Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 (8 of 2008) got repealed with effect from the 30th June, 2017 after the implementation of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) from 1st July, 2017;

And whereas in the light of above mentioned facts and judgments of the Apex Court and Punjab and Haryana High Court and legal provisions, it has been decided to issue the Haryana Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2024 under section 174 of the Haryana Goods and Services Act, 2017 (19 of 2017) to complete the pending proceedings under the Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 (8 of 2008);

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to the sub-section (2) of section 174 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) the Governor of Haryana hereby issues the following order namely:-

1. (1) This order may be called the Haryana Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2024.
- (2) It shall be deemed to have come in the force with effect from the 16th April, 2008.
2. (1) In this Order, unless the context otherwise requires;-
  - (a) "Act" means the Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 (8 of 2008);
  - (b) "Appellate Authority" means the authority as defined under Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003);
  - (c) "Authorized bank" means a Scheduled Bank or its subsidiary authorized by the State Government to receive payment of any dues, fee or amount payable under the Act or this Order;
  - (d) "Circle" means a tax circle in the concerned district demarcated under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) and the rules made thereunder, by Deputy Excise and Taxation Commissioner in-charge of the district, for the purpose of administration under the Act;
  - (e) "Form" means the form appended with this order;
  - (f) "Government Treasury" means a treasury or sub-treasury of Government or a branch or subsidiary of the State Bank of India situated in the local area in which the importer concerned has his place of business or the head office in the State, if there are branches and where any amount is recovered or collected, the local area in the State in which the amount is recovered or collected;
  - (g) "Revisional Authority" means the Authority as defined under the Haryana Value Added Tax Act, 2003(6 of 2003);
  - (h) "section" means the section of the Act;
  - (i) "Tribunal" means the Authority as defined under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003).

(2) Words and expressions used in this Order, but not defined here shall have the same meaning, as assigned to them in the Act or under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) and rules made thereunder.

3. (1) Every importer liable to get registered under section 4 read with sub-section (2) of section 3 shall make an application for registration to the assessing authority of the circle in Form ET-1 within thirty days of becoming liable for registration or from the date of publication of this Order in the Official Gazette, whichever is later.

(2) Each application for registration shall be accompanied by a receipt from the Government Treasury or crossed demand draft or pay order in favour of the assessing authority for one hundred rupees and such additional sum as is required to cover the additional place of business at the rate of fifty rupees for each copy.

(3) The assessing authority on receiving the application, shall, if the importer is already registered under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), Haryana General Sales Tax Act, 1973 (20 of 1973), shall forthwith, and in case of any other importer, if he is satisfied after making such enquiry as he thinks necessary that the particulars contained in the application are correct and complete, register the importer and grant a registration certificate in Form ET-2 and also grant a copy of such registration for every place of business within the State, other than the head office within the State mentioned therein. Such registration shall be held by the importer subject to the provisions of the Act and this order and the restrictions and conditions specified in that certificate.

(4) When the assessing authority is not satisfied that the particulars contained in the application are correct and complete, he shall reject the application for reasons to be recorded in writing:

Provided that such rejection shall not be made before giving the applicant, an opportunity of being heard in the matter.

(5) The Registration Certificate under sub-clause (3) of clause 3 of this Order shall be exhibited in a conspicuous place within the premises of each of business including the head office (to be declared by the importer), if any, mentioned in the certificate.

(6) Every registered importer who discontinues or transfers his business or otherwise gets his registration certificate cancelled shall forthwith surrender to the assessing authority the certificate of registration and the copies thereof, if any, granted to him.

(7) Where the Registration Certificate granted under this order is lost, destroyed, defaced or mutilated, a duplicate copy of the Registration Certificate may be granted by the assessing authority, if he is satisfied of such loss, destruction, defacement or mutilation etc.

(8) The registered dealers who had got migrated from the Haryana Goods and Services Tax Act, 1973 (10 of 1973) to Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) or had got registered under Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) as well as the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (3 of 2000) shall be considered as deemed Registered Importer under the Act if he is covered under the provisions of the Act or this Order. In such cases, the Tax Identification Number of the dealer issued under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) shall be considered as Registration Number of the said importer under the Act.

**4.** (1) Where the importer desires that the Registration Certificate granted to him under the Act to be amended, he shall submit an application for this purpose within thirty days of the contingency having arisen to the assessing authority setting out the specific matters in respect of which, he desires such amendment and the reasons, therefore, together with the registration certificate granted to him and such authority may, if satisfied with the reasons given, make such amendment as he thinks necessary, in the Registration Certificate and the copies thereof, if any, granted to him:

Provided that the amendment so made shall not be inconsistent with the provisions of the Act or this Order.

(2) The provisions of the Act or this Order shall apply in relation to such amended certificate and copies thereof as they apply in relation to the original certificate and copies thereof.

**5.** (1) The security required to be furnished under the Act, may be submitted by the importer in the following manner, namely:

- (a) by depositing as security in the Government Treasury, the amount fixed by the said authority; or
- (b) by depositing security amount in the Post Office Saving Bank and pledging the pass book to and depositing it with the said authority; or
- (c) by furnishing to the said authority a guarantee from a scheduled bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 ( Central Act 2 of 1934) (as amended), agreeing to pay the State Government, on demand, the amount of security fixed by the said authority; or
- (d) by furnishing personal bond with solvent surety/sureties for the amount of security to the satisfaction of the said authority in form ET-7 on a non-judicial paper of the appropriate value;
- (e) by furnishing such saving certificates or bonds or fixed deposit receipts as are issued by the Government of India, the State Government, or Reserve Bank of India or Scheduled Bank, from time to time, and pledging them to and depositing them with the said authority; or to be pledged to the Commissioner or any other officer authorized by him in this behalf.

(2) The security furnished under the Act shall be maintained in full so long as Registration Certificate continues to be in force.

(3) The security furnished may, in the event of default of payment of any tax, interest or penalty or any other amount due, be adjusted towards such tax, interest or penalty etc. The Assessing Authority may, in any case where such adjustment has been made, demand fresh security or additional security to make up the amount adjusted towards the outstanding dues:

Provided that no action under this sub-clause shall be taken unless the importer affected has been given a reasonable opportunity of being heard.

**6.** (1) In the case of an importer having more than one place of business in the State, the aggregate gross turnover of all such places of business shall be taken as the gross turnover of the business.

(2) All statements and returns prescribed in the Act or this Order shall, in the case of importer referred to in sub-clause (1), be submitted by the Head Office in the State to the assessing authority of the circle in which such Head Office is located and shall include the aggregate of turnover of all the branches of his business.

7. (1) Every registered importer and every importer whose application for registration is pending with the assessing authority shall submit a return for every quarter in Form ET-3 in duplicate to the assessing authority of the circle so as to reach him within a month after the close of the period to which the return relates:

Provided that the assessing authority of the circle may for the reasons to be recorded in writing direct any registered importer to file monthly returns:

Provided further that no such directions shall be issued without affording an opportunity of being heard to the importer:

Provided further also that every importer who discontinues or closes down his business at any time, shall submit to the assessing authority, the return for the period up to and inclusive of the date of discontinuance/closure within a period of thirty days from the date of such discontinuance/closure.

(2) Every importer, who submits a return under sub-clause (1) shall submit along with the return, tax payment receipt from the Government Treasury, or crossed demand draft or pay order in favour of the assessing authority for the full amount of tax due as per the provisions of the Act or this Order.

8. (1) Where an importer has failed to file a return within ninety days of its due date, the assessing authority shall, while making assessment to the best of its judgment, presume, in the absence of any evidence to the contrary, that the turnover of the importer for the period under assessment has not been less than that of during the corresponding period of the previous year or under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003).

(2) If, in any case, the assessing authority proposes to assess a turnover/figure different from that shown in the return submitted under the provisions of the Act or furnished in response to any notice or required under this order, it shall record its reasons in writing and shall intimate the assessee accordingly.

(3) After making an assessment, if the assessing authority finds that any amount is due from the importer after deducting tax paid under the provisions of the Act or this Order, he shall serve upon such importer a notice in form ET-4 and the assessee shall pay the sum demanded within the time and in the manner specified in the notice. If the tax due on the final assessment is lower than the tax already paid, it shall issue, at the option of the assessee, refund payment order in Form S.T.R. 34, prescribed under the Punjab Subsidiary Treasury Rules, or refund adjustment order in ET-5, for the amount of refund. If the final assessment is exactly equal to the tax already paid, the assessing authority shall furnish the assessee with a copy of an assessment order:

Provided that the excess tax/amount refundable to the assessee shall first be adjusted towards any other amount due from him under the Act, and for this purpose a refund adjustment order in Form ET-5 shall be issued:

Provided further that no amount in excess of One Lac Rupees shall be refunded without seeking prior approval of the Deputy Excise and Taxation Commissioner in-charge of the district who shall further seek approval of the Commissioner where the refundable amount is more than three Lacs rupees.

9. (1) In calculating the turnover liable to tax for a period, an importer may deduct from his gross turnover during that period----

- (a) the value of goods specified in Schedule 'A' of the Act;
- (b) the value of sugar received from another local area by way of purchase;
- (c) the value of goods which have, without use or consumption or sale, been delivered outside the local area;
- (d) the value of goods which have been subjected to tax once under the Act, either as such or in some other form;
- (e) the value of goods on which sales tax/value added tax (including purchase tax) has been paid or has become payable to the State, whether in the same form or in some other form;
- (f) the value of plant, machinery, equipment and tools, brought or received on lease for use in manufacture or processing of goods;
- (g) the value of goods brought or received in a local area for resale or for use or consumption therein in the manufacture or processing of goods, left in the stock whether as such or in different form lying with him in the local areas, except when the certificate of registration issued under the Act is cancelled; and
- (h) the value of plant, machinery, equipment and tools brought or received in the local area for use in manufacture or processing of goods, that has been capitalized; except when certificate of registration issued under the Act is cancelled;

Provided that he shall append to his returns for that period a list of such goods in respect of claims at (a) to (h) above (including plant, machinery, equipment and tools, wherever applicable) giving details of their description, quantity, value, date of entry into or as the case may be dispatch out of local area;

bill of sale, delivery note, purchase invoice, transfer note or other documents showing title or possession of such goods; goods receipt, railway receipt etc. by which such goods were received into or as the case may be dispatched out of local area or transported; and payment of sales tax/VAT (including purchase tax) or Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas Tax in respect of such goods, wherever so claimed.

(2) The assessing authority may require the importer to produce before it any record, book of account, statement, list, declaration, certificate or other relevant document in any form maintained by him in the normal course of business or required to be maintained by him under the provisions of the Act and this Order or any other law for the time being in force to satisfy itself about the genuineness and correctness of the lists specified under the Act or this Order or the entries made therein. It may also call for any relevant evidence from any other person to inquire into the genuineness and correctness of such lists or the entries made therein.

**10.** (1) An assessee may, in order to make payment of arrears of tax, interest or penalty by instalment, apply to the authority specified under this Order, within fifteen days from the date of service of demand notice in Form ET-4.

(2) The authorities for the purpose of the sub-clause (1) shall be:

- (a) the Commissioner, in case the payment of arrears by instalment exceeds five lakh rupees or the period within which arrears are to be paid by instalments exceeds twenty four months; and
- (b) The Deputy Excise and Taxation Commissioner, in all other cases.

(3) The authority specified for the said purpose under this clause may relax the period specified in sub-clause (1) in case where it finds that the delay in filing the application for grant of installments, has been for reasons beyond the control of the assessee.

(4) The granting of instalments under the sub-clause (2), shall be subject to the following conditions, namely:-

- (a) that the assessee furnishes adequate security to the satisfaction of the competent/concerned authority for payment of arrears by instalments;
- (b) that the assessee pays along with each permitted instalment interest chargeable under sub-section (5) of section 9 in respect of the amount of arrears outstanding up to the date of payment;
- (c) that the assessee makes a declaration to the effect that no other application has been made to the authorities other than the authorities specified under sub-clause (2) for payment of arrears by installments;

(5) The authority specified under sub-clause (2), to whom the application is made under sub-clause (1), may after making such inquiry as it deems fit, by an order in writing, subject to the conditions specified under sub-clause (4), permit an assessee to pay the arrears in such instalments and subject to such conditions, as may be specified in its Order.

(6) If the assessee contravenes any of the conditions specified in the order or in sub-clause (4) or commits any default in making payment in accordance with the provisions of the Act or this order, the whole of the sum remaining unpaid on the date of such default shall become recoverable at once in lump-sum together with the interest in accordance with the provisions of the Act and this Order.

**11.** (1) The tax, interest and penalty or any other amounts payable under the Act or this Order shall be paid by the importer -

- (i) by remittance into the Government Treasury; or
- (ii) by crossed demand draft or pay order in favour of the assessing authority.

(2) Every payment made under the Act or under this Order into the Government Treasury shall be accompanied by a challan in Form ET-6.

**12.** Where a refund is allowed by the assessing authority to a person, such a person shall make an application to the authority concerned, who shall issue refund within 180 days of the receipt of the application as per the provisions of the Act and this Order.

**13.** (1) Every registered importer and every person liable to get himself registered under the Act shall keep and maintain a true and correct account of his daily transactions showing the value of goods entering into a local area.

(2) Every such importer or person shall keep separate purchase and sale account in respect of goods.

(3) Every such importer or person shall keep the current books of accounts at the place or places of business entered in the Registration Certificate.

(4) Every such importer or person shall maintain day to day stock account in respect of each goods and each such variety of goods which is taxable at different rates. The stock account shall contain particulars of purchase or receipt, use or consumption, sale or dispatch and balance stock of goods.

(5) Every importer shall maintain subsidiary accounts of stock for each branch, depot or godown. Every branch shall also maintain the stock accounts in respect of its own transactions in the form adopted for this purpose by its Head Office.

(6) The account books maintained by importer shall be produced before Assessing Authority as and when required by a notice in this behalf.

**14.** (1) All entries in all forms, registers and other documents prescribed under the Act or this Order shall be made in ink or computer printed;

Provided that where more than one copy of form, declaration, return, register or other documents has to be filled or written at the same time, entries may be made by a ball point pen or typewriter or a computer.

(2) No entry in such forms, register and other documents shall be erased or overwritten. Incorrect entries shall be scored out under attestation and correct entry shall be recorded.

**15.** Subject to the other provisions of the Act and this Order, the provisions of Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) relating to appeal, review, revision, reference, rectification or clerical and arithmetical mistakes, power to take evidence on oath, power to determine as to who is a importer, power to call for information from banking companies etc., power to transfer proceedings, delegation of powers, attendance through authorized agents, information to be furnished regarding change of business, treatment of documents furnished by an importer/assessee as confidential and other related matters, shall apply, mutatis mutandis, accordingly, and for this purpose an importer/assessee under this Act shall possess the same rights and be under obligation to discharge the same liabilities as an importer under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003).

**16.** The Government shall, while allocating/appropriating the tax collected under the Act for the purposes specified in sub section (1) of section 25, take into consideration the recommendations of the Haryana Trade, Commerce and Industry Development Board constituted under section 26 of the Act.

## FORM ET-1

[see clause 3(1)]

**Application for the grant of a registration certificate as an importer under the Haryana Tax on Entry of into Local Areas Act, 2008 (8 of 2008)**

To

The Assessing Authority.

Circle \_\_\_\_\_,

District

I.....son/wife of..... carrying on business whose particulars are given below, hereby apply for registration under section 4 of the Haryana Tax on Entry of goods into Local Areas Act, 2008 (8 of 2008).

1.	Name and full postal address of the applicant (if there is a trade name, the trade name shall also be given).	
2.	Name and address of the Manager of the business, if a Manager has been so appointed.	
3.	Name and address and status of the person who signs this application (as regards status, state whether proprietor, manager, director, or partner, etc.).	
4.	Name and full postal address of the Head Office with particulars of building name and number, ward name and number, road name, street name, etc. Mobile number, Fax number, e-mail address, Internet site address, if any.	
5.	Name and full postal address of all the other places of business in the municipal area or elsewhere in the State with particulars of building name and number, ward name and number, road name, street name, etc., for each place of business (if the space in this column is found to be insufficient, additional sheet may be used and duly signed).	
6.	Complete list of godowns in which the goods are stored and address of every such godown.	
7.	Date of commencement of business and nature of business.	
8.	Date on which the applicant has become liable to pay tax for the first time.	
9.	Particulars of the Registration Certificate under the Haryana Value Added Tax Act, 2003(6 of 2003). (i) Tax payer's identification number (ii) Date of Validity	
10.	Estimated annual tax liability under the Act.	
11.	The accounting year followed by the applicant	
12.	Whether the applicant is a proprietor, firm, company, society, club, association of persons, Hindu undivided family, or trust, etc. (here give full description).	

13	The total value of purchases/stock receipts of goods in the year preceding that to which the application is submitted.	
14	Actual value of purchases/stock receipts of goods in the year upto the date of submission of the application.	
15	Amount of registration fee paid with particular of Receipt No. and date	
16	Amount of fee paid for copies of certificate for the other places of business with particulars of Receipts No. and date, Challan No. and date, Cheque No. and date/name of the Treasury/ Bank/Reference No. of the digital payment etc.	
17	Name(s) and address (es) of the proprietors, partners, members, all persons having any interest in the business (additional sheets with the following columns shall be used, if necessary).	

Serial	Name in full of	Name of the father	Age	Permanent address of each person of each person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Present Postal Address of each Person	Extent of interest of each person in the business	Signature of each person	Name, address signature of witness attesting signature	
(6)	(7)	(8)	(9)	

**DECLARATION**

I, .....Son/Wife of..... hereby declare that to the best of my knowledge and belief the information contained in this application given above are true and correct.

Place:

Date:

Signature.....

Full Name.....

Address.....

Status.....

(as given in Column 3)

(For official use by the assessing authority)

Date of receipt of application:

Nature of order passed by the assessing authority:

Date of order:

Registration Certificate No..... if issued:

Date of issue of registration certificate:

Signature of Assessing Authority  
with date

## FORM ET-2

*[see clause 3(3)]*

## CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration Number. \_\_\_\_\_

This is to certify that M/s..... whose place of business/Head Office is situated at..... has been granted a registration under section 4 of the Haryana Tax on Entry of goods into Local Areas Act, 2008 ( 8 of 2008), subject to the provisions of the said Act and this Order with following conditions:-

1.
  - (1) This certificate should be exhibited at a conspicuous place within the premises of the business.
  - (2) A correct account should be kept of the daily transactions at the place of business or additional business places.
  - (3.) The registered importer shall afford all facilities for the checking of his stock and shall, at all reasonable times, produce for inspection accounts or other documents and shall furnish fully and correctly any information in his possession as may be required for the purpose of the Act or this order by any officer empowered in this behalf.
  - (4) The prescribed statements and returns should be sent to the assessing authority of the circle in the prescribed time.
  - (5) This registration certificate should not be transferred or sold nor should it be amended without the permission of the assessing authority which should be applied for and obtained.
  - (6) All corrections in this certificate should be made and attested by the assessing authority.
  - (7) The registered importer shall be responsible for all the acts of his manager, agent or servant.
2. The registered importer has additional places of business as noted below:-
  - (a)
  - (b)
  - (c)
  - (d)
3. This Registration Certificate is valid from. ....until cancelled.
4. The holder of this registration certificate shall be liable to pay tax with effect from(date)\_\_\_\_\_ and shall file the tax returns and pay tax due according to such returns on quarterly basis so long as he remains liable to pay tax unless directed otherwise under the Act.

Date:

Seal

(Signed)

Assessing Authority

## FORM ET-3

[see clause 7(1)]

Return of turnover and tax payable

[to be submitted in duplicate]

Return for the period from.....to.....

1. Personal details (PAN, Contact No, Email ID etc.)
2. Registration Certificate No.:
3. Name and full address of the importer:
4. **Computation of liability to pay tax for the return period--**

**Goods--**

- (1) Description of goods forming part of turnover (State the main five only)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Item

Amount (In Rs.)

- (2) **Gross turnover—**

- (a) Opening stock carried forward from the previous period (See 1st proviso to clause (g) of section 8 of the Act): --

- (b) Aggregate of value of goods received on entry into a local area including goods for sale:  
[see clause (q) of section 2 of the Act] -----

- (3) Total of 2 (a) and 2(b):

Item \_\_\_\_\_ Amount (In Rs.) \_\_\_\_\_

**Deductions [see clause 9] --**

- (4)
  - (a) Value of goods specified in Schedule 'A' appended to the Act:-
  - (b) The value of sugar received from another local area, by way of purchase:
  - (c) Value of goods which have, without consumption, use or sale, been delivered outside the local area:
  - (d) The value of goods which have been subjected to tax once under the Act, either as such or in some other form:
  - (e) the value of goods on which sales tax has been paid or has become payable to the State, whether in the same form or in some other form:
  - (f) the value of plant, machinery, equipment and tools, brought or received on lease for use manufacture or processing of goods:
  - (g) the value of goods brought or received in a local area for resale or for use or consumption in the manufacture or processing of goods, left as such or in different form including goods in process or processed or manufactured lying with him in the stock in the local area, except when the certificate of registration issued under the Act is cancelled:
  - (h) the value of plant, machinery, equipment and tools brought or received in a local area for use in manufacture or processing of the goods, that has been capitalized, except when the certificate of registration issued under the Act is cancelled:
  - (i) Any other deduction claimed under the Act or this Order (specify the deduction quoting the relevant provision of the Act or the Order and attach detail with the return):

- (5) Sum of 4 (a) to 4 (i): \_\_\_\_\_

**Taxable turnover:**

- (6) Value of goods liable to tax (Item 3 minus item 5):--

**Tax Payable:**

(7) Taxable turnover multiplied by rate of tax applicable under the Act: \_\_\_\_\_

**Payment of tax:**

(8) Mode of Payment--

Sr.No.	Tax Paid/Amount (in Rs.)	Date	Name of Treasury and Treasury Receipt No.	Demand Draft No.	Online Payment Reference No./Debit Entry No.
--------	-----------------------------	------	--	---------------------	--

(9) Balance due, if any (item 6 minus item 7): \_\_\_\_\_

**DECLARATION**

I.....Son of/Wife of ..... do solemnly declare that the information furnished in the above statement is true and complete to the best of my knowledge and belief.

Place:

Date:

Signature\_\_\_\_\_

Full Name\_\_\_\_\_

Status\_\_\_\_\_

**16. FORM ET-4***[see clause 8(3)]***Notice of assessment and demand under section 9 of Haryana Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2008 (8 of 2008).**

District

Dated

No.....

To

You are hereby informed that during the year..... you have been assessed/reassessed to tax as under: -

Value of goods determined as liable to tax: Rs.

Tax and interest assessed: -

(a) Tax	Rs.
(b) Interest	Rs.
(c) Penalty imposed, if any	Rs.
Total (A, B and C)	Rs.
(d) Less amount paid already	Rs.
(e) Net amount due	Rs.

You are hereby directed to pay the sum of Rs.....(in Figures) rupees.....(in words), into Govt. treasury/State Bank of India or its subsidiary or any scheduled bank or its branch on or before (date)..... and furnish the receipt of proof of payment in this office on or before (date).....failing which the said amount shall be recoverable from you as an arrears of land revenue.

A challan in form ET-6 is enclosed for the purpose.

(Signature)

Assessing Authority

Date

Seal of Assessing Authority

District

## FORM ET-5

*[see clause 8(3)]***Refund Adjustment Order**

Book No.....

Voucher No.....Refunds

To

.....

.....

1. Certified with reference to the assessment records of the importer (name) .....bearing registration No.....of..... district for the periods from.....to..... that a refund of Rs.....(in figures)rupees.....(in words) is due to (name)..... under the Haryana Tax on Entry of goods into Local Areas Act,2008(8 of 2008).
2. Certified that the tax concerning which this refund is allowed has been credited into the treasury.
3. Certified that no refund order regarding the sum in question has previously been granted and this order of refund has been entered in the original assessment file/disposal register under my signatures.
4. This refund will be adjusted towards the amount of tax due from the said importer for the period from..... To..... Or any subsequent month/quarter.
5. The importer shall attach this order with the return to be furnished by him for the month against which the adjustment is desired.

Signature

Dated

Assessing Authority

Seal of Assessing Authority

District

**FORM ET-6***[see clause 11(2)]***CHALLAN****PART-A****(to be retained in the treasury)**

Treasury

Sub Treasury Branch/Subsidiary of the State Bank of India/Scheduled Bank or Any branch thereof.

Invoice of Tax etc. paid into and credited under the head of the account "0042-Taxes on Goods and Passengers (1) 106-Tax on entry of Goods into Local Area: (3)- Haryana Tax on Entry of goods into Local Area" under the Haryana Tax on Entry of goods into Local Areas Act, 2008 (8 of 2008).

By whom Tendered	Name, address of the person with R.C./license No. on whose behalf money is paid	Payment on account of	Amount
---------------------	---	-----------------------	--------

Rs.

- (i) tax according to the returns.....
- (ii) tax assessed.....
- (iii) Interest.....
- (iv) Penalty.....
- (v) Composition.....
- (vi) Registration.....
- (vii) licence fee.....
- (viii) Security.....
- (ix) other fee.....
- (x) Total.....

Dated the

Certified that all the particulars given above are correct.

\*Entry tax clerk.....

\*Receive and grant receipt.....

\*Assessing Authority/Circle In – charge.....

Signature of the importer

Treasury Accountant

Sub-Treasury Officer

Agent of the Branch/Subsidiary of the State Bank of India/Scheduled bank  
or branch thereof

Amount received.....

Seal of assessing

Authority/circle in-charge

Treasurer

Stamp of the Treasury/Bank

Officer Sub-Treasury Officer Treasurer State Bank of India/Scheduled bank or branch thereof

\*Not required to be signed by the Entry Tax Clerk/assessing authority in case of voluntary payment by an importer or depositor.

Part B: To be returned to the Deputy Excise and Taxation Commissioner in-charge of the District.

Part C: To be attached by the importer with the application/return.

Part D: To be retained by the importer.

Note:- Parts B, C and D of ET-6 are similar to Part A. Hence not reproduced.

**FORM ET-7***[see clause 5(1)(d)]***Bond**

Know all men by these presents that I/we..... (Full Name and address) with registration certificate No., if any..... am/are held and firmly bound to the Governor of Haryana (hereinafter referred to as "the Government" which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, include his successor-in-office and assigns) in the sum of Rs..... (Rupees in words ..... ) (hereinafter referred to as the said sum) to be paid to the Government on demand, for which payment will and truly to be made. I/we bind myself/ourselves/my/our heirs, executors, administrators and legal representatives by these presents.

Whereas the above bounden has been required by the assessing authority/appellate authority ..... (Name of place) to furnish security for the said sum for the purpose of securing the payment of any amount payable by him/them under the Haryana Tax on Entry of goods into Local Areas Act, 2008 (hereinafter referred to as the "Act") and to indemnify the Government against all losses, costs or expenses which the Government, may, in any way, suffer, sustain or pay by reason of the omission, default or failure or insolvency of the above bounden or any person or persons acting under or for him/them to pay the said sum in the manner prescribed under the Act;

Now, the condition of the above written bond is such that if the above bounden, his/their heirs, executors, administrator and legal representatives or any person acting under or for him/them pays the full amount due in the manner prescribed under the Act. Such demand to be in writing and to be served upon the above bounden, his/their heirs, executors, administrators and legal representatives or any other person acting under or for him/them in the manner prescribed under the Act and shall also at all times indemnify and save the Government from all and every loss, cost of expenses which have been or shall or may at any time hereafter during the period in which the above bounden is held liable to pay any sum due under the Act, be caused by reason of any person acting under or for him/them, then this obligation shall be void and be of no effect, otherwise the same shall be and remain in full force and effect and it is hereby further agreed that the in event of the death/partition/disruption/dissolution/winding up or the final cessation of the liability under the Act or the ROD issued thereunder of the above bounden, this bond, shall remain with the aforesaid authority for recovering any sum that may be payable by the above bounden or any loss, cost or expenses that may have been sustained, incurred on insolvency of the above bounden his/their heirs, executors, administrators and legal representatives and which may not have been discovered until after the above bounden's death/partition/disruption/dissolution/winding up or final cessation of his/their liability under the Act or the ROD issued thereunder.

Provided always that without prejudice to any other right or remedy for recovering any sum due under the Act or loss or damage as aforesaid, it shall be open to the Government to recover the amount payable under this bond as arrears of land revenue.

In witness whereof the said .....(Full Name) has hereunto set his/their hand(s) this..... day of.....signed and delivered by the above named in the presence of witness:

1. .... Signature.....
2. .... Status.....
3. We (1) .....  
(2) .....

(Name and full address of the sureties) hereby declare ourselves to be sureties for the above bounden and guarantee that he/they shall do and perform all that he/they has/have above undertaken to herein, we hereby bind ourselves jointly and severally to pay the Government the sum of Rs..... (Rupees.....)in which the above bounden has bound himself or such other lesser sum as shall be deemed to be sufficient by the assessing authority to recover to any sum payable by the above bounden and remaining unpaid and also to recover any loss, damage, cost of expenses, which the Government may sustain, incur or pay by reasons of such omission, default or failure;

And we agree that the Government may without prejudice to any other rights or remedies of the Government, recover the said sum from us, jointly and severally, as arrears of land revenue;

And we also agree that neither of us shall be at liberty to terminate this surety bond except upon giving to the assessing authority six calendar months notice in writing of our intention to do so and our joint and several liability under this bond shall continue in respect of all acts, omissions, defaults, failure and insolvencies on the part of the bounden until the expiration of the said period of six months.

Name, complete address and Signatures of Witnesses:

1. Signature

Permanent Address.....

2. Signature

Permanent Address.....

DEVINDER SINGH KALYAN,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.